

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी 2025 — माघ 1, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक 749/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 09-1-2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 5 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन)
अधिनियम, 2024.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम
एवं प्रारंभ

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलाएगा।
- (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र 7 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 9 की उप-धारा (1) में, वाक्यांश "मानवीय उपभोग के लिए मदयसारिकपान" के पश्चात्, वाक्यांश "और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए मदयसारिकपान के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है," अंतःस्थापित किया जाए। **धारा 9 का संशोधन।**
3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, शब्द एवं अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित किया जाए। **धारा 10 का संशोधन।**
4. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :— **धारा 11 का संशोधन।**
- "11क. **साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहित नहीं किए गए या कम उद्गृहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति.**— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि—
- (क) माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर राज्य कर के उद्गृहण (उसके गैर उद्गृहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और
- (ख) ऐसी प्रदायों, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या हैं—
- (i) उन मामलों में, जहाँ उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उद्गृहीत नहीं किया गया था या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर; या
- (ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उद्गृहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम हैं,

तो राज्य सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसे प्रदायों पर संदेय संपूर्ण राज्य कर

या ऐसे प्रदायों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, परंतु उक्त पद्धति हेतु उन प्रदायों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है या उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था या कम उद्गृहीत किया जा रहा है या कम उद्गृहीत किया जा रहा था।”

धारा 13 का संशोधन। 5.

मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में,—

(एक) खंड (ख) में, शब्द “प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए” के स्थान पर, शब्द “उन मामलों में, जहाँ बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए;” प्रतिस्थापित किया जाए;

(दो) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) उन मामलों में, जहाँ बीजक, प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख;”

(तीन) प्रथम परंतुक में, शब्द तथा चिन्ह “या खंड (ख) के पश्चात्, शब्द तथा चिन्ह “या खंड (ग)” अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 16 का संशोधन। 6.

मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

“(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017—18, 2018—19, 2019—20 और 2020—21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और

तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहत किया जाता है और जहाँ बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उप-धारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,—

(एक) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है; या

(दो) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहाँ ऐसी विवरणी, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, फाइल की जाती है :

परंतु यह कि भुगतान किये गये सभी कर या इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय नहीं लिया जाएगा जिसका इस प्रकार भुगतान नहीं किया गया होता या जो प्रत्यावर्तित नहीं किया गया होता, धारा 6 के अधीन सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त होगा।”

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के खंड (झ) में, शब्द तथा अंक “धारा 74, धारा 129 और धारा 130” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी के संबंध में धारा 74” प्रतिस्थापित किया जाए। **धारा 17 का संशोधन।**
8. मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” **धारा 21 का संशोधन।**

अंतःस्थापित किया जाए।

- धारा 30 का संशोधन।** 9. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
- “परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं।”
- धारा 31 का संशोधन।** 10. मूल अधिनियम की धारा 31 में,—
- (एक) उप-धारा (3) के खंड (च) में, शब्द “कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो” के पश्चात्, शब्द “ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए” अंतःस्थापित किया जाए ;
- (दो) उप-धारा (3) के खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
- “स्पष्टीकरण.— खंड (च) के प्रयोजनार्थ, “प्रदायकर्ता, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है” पद में ऐसा प्रदायकर्ता सम्मिलित होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है।”
- धारा 35 का संशोधन।** 11. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (6) में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित किया जाए।
- धारा 39 का संशोधन।** 12. मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—
- “(3) धारा 51 के अधीन, स्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा :
- परंतु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान

कोई कटौतियां की गई हों अथवा नहीं।”

13. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) के खंड (ग) में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित की जाए। **धारा 49 का संशोधन।**
14. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित की जाए। **धारा 50 का संशोधन।**
15. मूल अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (7) में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित की जाए। **धारा 51 का संशोधन।**
16. मूल अधिनियम की धारा 54 में,— **धारा 54 का संशोधन।**
 - (एक) उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक का लोप किया जाए ;
 - (दो) उप-धारा (14) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - “(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल के प्रदाय की शून्य रेटेड के मददे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य रेटेड प्रदाय के मददे संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहाँ माल की ऐसी शून्य रेटेड प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यक्षीन है।”
17. मूल अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (3) में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित की जाए। **धारा 61 का संशोधन।**
18. मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74 क” अंतःस्थापित की जाए। **धारा 62 का संशोधन।**
19. मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित की जाए। **धारा 63 का संशोधन।**
20. मूल अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) में, शब्द तथा **धारा 64 का**

- संशोधन। अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए।
- धारा 65 का 21. मूल अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (7) में, शब्द तथा संशोधन। अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए।
- धारा 66 का 22. मूल अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (6) में, शब्द तथा संशोधन। अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात्, शब्द तथा अंक "या धारा 74क" अंतःस्थापित की जाए।
- धारा 70 का 23. मूल अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) के पश्चात्, संशोधन। निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :-
- “(1क) उप-धारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे और इस प्रकार उपस्थित हाने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।”
- धारा 73 का 24. मूल अधिनियम की धारा 73 में,— संशोधन।
- (एक) पार्श्व शीर्षक में, शब्द “असंदत्त कर” के पूर्व, शब्द तथा अंक “वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित” अंतःस्थापित किया जाए ;
- (दो) उप-धारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-
- “(12) इस धारा के उपबंध, वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।”
- धारा 74 का 25. मूल अधिनियम की धारा 74 में,— संशोधन।
- (एक) पार्श्व शीर्षक में, शब्द “असंदत्त कर” के पूर्व शब्द तथा अंक “वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित” अंतःस्थापित किया जाए ;

(दो) उप-धारा (11) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(12) इस धारा के उपबंध, वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।”;

(तीन) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाए।

26.

मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :-

नवीन धारा
74क का
अंतःस्थापन।

“74क. वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या कर से संबंधित किसी कारण से गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.— (1) जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहाँ इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्गृहणीय शास्ति का संदाय करे, को सूचना की तामील करेगा :

परंतु यह कि कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर एक हजार रुपए से कम है, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए,

जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उप-धारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।

- (3) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन किसी अवधि क लिए सूचना जारी की गई है, वहाँ समुचित अधिकारी, कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा।
- (4) ऐसे कथन की तामील, उप-धारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न, ऐसी कर अवधियों के लिए विश्वास किए गए आधार, पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, सूचना की तामील समझी जाएगी।
- (5) उस मामले में, जहाँ कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहाँ शास्ति,—
 - (एक) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपए, जो भी उच्चतर हो, होगी ;
 - (दो) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी।
- (6) समुचित अधिकारी, कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति

द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा।

- (7) समुचित अधिकारी, उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उप-धारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा:

परंतु यह कि, जहाँ समुचित अधिकारी, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहाँ आयुक्त या समुचित अधिकारी की श्रेणी में वरिष्ठ आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, परंतु जो राज्य कर संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न हो, उप-धारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, उक्त कालावधि को अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा।

- (8) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहाँ कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

(एक) उप-धारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर की रकम का संदाय ब्याज सहित कर सकेगा और ऐसे संदाय के विषय में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उप-धारा (1) के अधीन किसी सूचना या उप-धारा (3) के

अधीन कथन की तामील नहीं करेगा ;

(दो) कारण बताओं सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(9) जहा कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों, जहाँ कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या उपयोग किया गया है, वहाँ कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

(एक) उप-धारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, उप-धारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा;

(दो) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी;

(तीन) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे

कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर, उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी।

- (10) जहाँ समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहाँ उप-धारा (8) के खंड (एक) या उप-धारा (9) के खंड (एक) के अधीन संदत्त रकम, वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहाँ ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, तो वह उप-धारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अग्रसर होगा।
- (11) उप-धारा (8) के खंड (एक) या खंड (दो) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (5) के खंड (एक) के अधीन वहाँ शास्ति संदेय होगी, जहाँ स्व-निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संग्रहीत कोई रकम, ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है।
- (12) वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (एक) “उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ” पद में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियाँ सम्मिलित नहीं होंगी;
- (दो) जहाँ उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियाँ, इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहाँ धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी।

स्पष्टीकरण 2.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “छिपाना” पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है जिसके द्वारा कराधेय

व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में, या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करे।

धारा 75 का 27. संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 75 में,—

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द तथा अंक “धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)” के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह “या 74क की उप-धारा (2) और (7)” अंतःस्थापित की जाए;

(दो) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(2क) जहाँ किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उप-धारा (5) के खंड (दो) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उप-धारा (5) के खंड (एक) के अधीन होगा।” ;

(तीन) उप-धारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(10) न्याय निर्णयन कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उप-धारा (10) या धारा 74 की उप-धारा (10) या धारा 74क की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है।” ;

(चार) उप-धारा (11) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह “धारा 74 की उपधारा (10) में” के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह “या धारा 74क की उप-धारा (7) में” अंतःस्थापित किया जाए;

- (पाँच) उप-धारा (12) में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित की जाए ;
- (छः) उप-धारा (13) में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित किया जाए।
- 28.** मूल अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक तथा चिन्ह “या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)” के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह “या 74क की उप-धारा (2) और उप-धारा (7)” अंतःस्थापित किया जाए। **धारा 104 का संशोधन।**
- 29.** मूल अधिनियम की धारा 107 में,— **धारा 107 का संशोधन।**
- (एक) उप-धारा (6) के खंड (ख) के परंतुक में, शब्द “पच्चीस” के स्थान पर, शब्द “बीस” प्रतिस्थापित किया जाए;
- (दो) उप-धारा (11) के द्वितीय परंतुक में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित किया जाए।
- 30.** मूल अधिनियम की धारा 112 में,— **धारा 112 का संशोधन।**
- (एक) उप-धारा (1) में, वाक्यांश “उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से,” के पश्चात्, वाक्यांश “या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो” अंतःस्थापित किया जाए;
- (दो) उप-धारा (3) में, वाक्यांश “उक्त आदेश परित किया गया है” के पश्चात्, वाक्यांश “या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो” अंतःस्थापित किया जाए;
- (तीन) उप-धारा (6) में, वाक्यांश “अपील स्वीकार कर

सकेगा” के पश्चात्, वाक्यांश, चिन्ह तथा अंक “या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर आवदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा” अंतःस्थापित किया जाए;

(चार) उप-धारा (8) के खंड (ख) में,—

(क) शब्द “बीस प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “दस प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) शब्द “पचास करोड़ रुपए” के स्थान पर, शब्द “बीस करोड़ रुपए” प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 122 का संशोधन। 31.

मूल अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1ख) में, वाक्यांश “कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक” के स्थान पर, वाक्यांश तथा अंक “कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है,” प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 127 का संशोधन। 32.

मूल अधिनियम की धारा 127 में, शब्द तथा अंक “धारा 73 या धारा 74” के पश्चात्, शब्द तथा अंक “या धारा 74क” अंतःस्थापित किया जाए।

नवीन धारा 128क का अंतःस्थापन। 33.

मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“128क. कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन.— (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कोई रकम संदेय है,—

(क) धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उप-धारा (3) के अधीन जारी कथन और जहाँ धारा 73 की उप-धारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा 73 की उप-धारा (9) के अधीन पारित आदेश और जहाँ धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उप-धारा (11) या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहाँ धारा 113 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है,

1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की कालावधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समाप्त हुई समझी जाएंगी:

परंतु यह कि जहाँ धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उप-धारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगा:

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहाँ आवेदन धारा 107 की उप-धारा (3) या धारा 112 की उप-धारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उप-धारा (1) के अधीन या धारा 118 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहाँ खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही आरंभ की जाती है, वहाँ इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है:

परंतु यह भी कि जहाँ ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

- (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मददे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी।
- (3) उप-धारा (1) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है।
- (4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उप-धारा के अधीन कार्यवाहियाँ समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहाँ धारा 107 की उप-धारा (1) या धारा 112 की उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उप-धारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।”

धारा 171 का 34. संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 171 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक तथा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस विषय में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी, वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के परिणामस्वरूप है।

स्पष्टीकरण 1.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, “परीक्षा के लिए अनुरोध” से अभिप्रेत है कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा

फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्राधिकारी” पद में “अपील अधिकरण” सम्मिलित होगा।”

35.

मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 पश्चात् एवं स्पष्टीकरण-1 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

**अनुसूची 3
का संशोधन।**

“9. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए बीमाकर्ता को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रदाय की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप।

10. इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि पुनःबीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन सहित संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुनः बीमाकर्ता की सेवाएं, जिसके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन, पुनःबीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम से कटौती की जाती है।”

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्रमांक 749/डी. 07/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 5 of 2025)

**THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) ACT, 2024.**

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

**Short title and
commencement.**

(1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force on such date the State Government may, by notification from the date of publication of Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

**Amendment of 2.
Section 9.**

In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017) (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1) of Section 9, after the protasis “alcoholic liquor for human consumption”, the protasis “, un-denatured extra neutral alcohol and rectified spirit used for manufacture of

alcoholic liquor, for human consumption” shall be inserted.

3. In sub-section (5) of Section 10 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted.

**Amendment of
Section 10.**

4. After Section 11 of the Principal Act, the following Section shall be added, namely:—

**Amendment of
Section 11.**

“11A. Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short-levied as a result of general practice.- Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that—

(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of state tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and

(b) such supplies were, or are, liable to,—

(i) state tax, in cases where according to the said practice, state tax was not, or is not being, levied, or

(ii) a higher amount of state tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the state tax payable on such supplies, or, as the case may be, the state tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.”

**Amendment of 5.
Section 13.**

In sub-section (3) of Section 13 of the Principal Act,—

- (i) in clause (b), for the words “by the supplier:”, the words “by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or” shall be substituted;
- (ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient;”

- (iii) in the first proviso, after the words and symbol “or clause (b)”, the words and symbol “or clause (c)” shall be inserted.

6. After sub-section (4) of Section 16 of the Principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, the following sub-sections shall be added, namely:—

**Amendment of
Section 16.**

“(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under Section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.

- (6) Where registration of a registered person is cancelled under Section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under Section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where a availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under Section 39,—

- (i) filed up to thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or
- (ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration, whichever is later:

Provided that no refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had Section 6 been in force at all material times.”

**Amendment of
Section 17.**

7.

In clause (i) of sub-section (5) of Section 17 of the Principal Act, for the words and figures “Sections 74, 129 and 130”, the words and figures “Section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24” shall be substituted.

**Amendment of
Section 21.**

8.

In Section 21 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or

Section 74”, the words and figures “or Section 74A” shall be inserted.

9. After the proviso of sub-section (2) of Section 30 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:—

**Amendment of
Section 30.**

“Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”

10. In Section 31 of the Principal Act,—
- (i) in clause (f) of sub-section (3), after the words and figure “of Section 9 shall”, the words, “, within the period as may be prescribed,” shall be inserted;
- (ii) after clause (g) of sub-section (3), the following Explanation shall be inserted, namely:—

**Amendment of
Section 31.**

“Explanation.—For the purposes of clause (f), the expression “supplier who is not registered” shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under Section 51.”

11. In sub-section (6) of Section 35 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figures “or Section 74A” shall be inserted.

**Amendment of
Section 35.**

- | | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| Amendment of
Section 39. | 12. | <p>For sub-section (3) of Section 39 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—</p> <p>“(3) Every registered person required to deduct tax at source under Section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:</p> <p>Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.”</p> |
| Amendment of
Section 49. | 13. | <p>In clause (c) of sub-section (8) of Section 49 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figures “or Section 74A” shall be inserted.</p> |
| Amendment of
Section 50. | 14. | <p>In the proviso of sub-section (1) of Section 50 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figures “or Section 74A” shall be inserted.</p> |
| Amendment of
Section 51. | 15. | <p>In sub-section (7) of Section 51 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted.</p> |
| Amendment of
Section 54. | 16. | <p>In Section 54 of the Principal Act,—</p> <p>(i) second proviso of sub-section (3) shall be omitted;</p> |

(ii) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(15)Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.”

- | | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| 17. | In sub-section (3) of Section 61 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted. | Amendment of
Section 61. |
| 18. | In sub-section (1) of Section 62 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted. | Amendment of
Section 62. |
| 19. | In Section 63 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted. | Amendment of
Section 63. |
| 20. | In sub-section (2) of Section 64 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted. | Amendment of
Section 64. |

- | | | |
|-------------------------------------|------------|---|
| Amendment of
Section 65. | 21. | In sub-section (7) of Section 65 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted. |
| Amendment of
Section 66. | 22. | In sub-section (6) of Section 66 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted. |
| Amendment of
Section 70. | 23. | <p>After sub-section (1) of Section 70 of the Principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:—</p> <p>“(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required.”</p> |
| Amendment of
Section 73. | 24. | <p>In Section 73 of the Principal Act,—</p> <p>(i) in the marginal heading, after the words “Determination of tax”, the words and figures “, pertaining to the period up to Financial Year 2023-24,” shall be inserted;</p> <p>(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be added, namely:—</p> <p>“(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax</p> |

pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.”

25.

In Section 74 of the Principal Act,—

(i) in the marginal heading, after the words “Determination of tax”, the words and figures, “pertaining to the period up to Financial Year 2023-24,” shall be inserted;

(ii) after sub-section (11) and before Explanation 1, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.”

(iii) the Explanation 2 shall be omitted.

26.

After Section 74 of the Principal Act, the following Section shall be added, namely :—

“74A. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onward.- (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so

Amendment of Section 74.

Insertion of New Section 74A.

paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under Section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

- (2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.
- (3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer

may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

- (4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.
- (5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,—
 - (i) For any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent. of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

- (ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.
- (6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.
- (7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend

the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under Section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made there under;

(ii) pay the said tax along with interest payable under Section 50 within sixty

days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under Section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or

- the rules made thereunder;
- (ii) pay the said tax along with interest payable under Section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent. of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;
- (iii) pay the tax along with interest payable thereon under Section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.
- (10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.
- (11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8),

penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

- (12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1.—For the purposes of this Section,—

- (i) the expression “all proceedings in respect of the said notice” shall not include proceedings under Section 132;
- (ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under Sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2.—For the purposes of this Act, the expression “suppression” shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made there under, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.”

27.

In Section 75 of the Principal Act,—

- (i) in sub-section (1), after the word and figure “Section 74”, the words, figures and symbol “or sub-section (2) and (7) of Section 74A” shall be inserted;
- (ii) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of Section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause

**Amendment of
Section 75.**

- (i) of sub-section (5) of Section 74A.”
- (iii) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - “(10)The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of Section 73 or in sub-section (10) of Section 74 or in sub-section (7) of Section 74A.”;
- (iv) in sub-section (11), after the word and figure “Section 74”, the words, figures and symbol “or sub-section (7) of Section 74A” shall be inserted;
- (v) in sub-section (12), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted;
- (vi) in sub-section (13), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted.

- 28.** In Explanation of sub-section (1) of Section 104 of the Principal Act, after the word and figure “Section 74”, the words, figures and symbol “or sub-section (2) and (7) of Section 74A” shall be inserted. **Amendment of Section 104.**
- 29.** In Section 107 of the Principal Act,—
(i) in proviso of clause (b) of sub-section (6), for the word “twenty-five”, the word “twenty” shall be substituted;
(ii) in the second proviso of sub-section (11), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figure “or Section 74A” shall be inserted. **Amendment of Section 107.**
- 30.** In Section 112 of the Principal Act,—
(i) in sub-section (1), after the protasis “from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal”, the protasis “; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later.” shall be inserted;
(ii) in sub-section (3), after the protasis “from the date on which the said order has been passed”, the protasis “;or the date, as may be notified by the Government, on the **Amendment of Section 112.**

recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later,” shall be inserted;

(iii) in sub-section (6), after the protasis and figure “after the expiry of the period referred to in sub-section (1)”, the protasis and figure “or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)” shall be inserted;

(iv) in clause (b) of sub-section (8),—

(a) for the words “twenty per cent.”, the words “ten per cent.” shall be substituted;

(b) for the words “fifty crore rupees”, the words “twenty crore rupees” shall be substituted.

**Amendment of 31.
Section 122.**

In sub-section (1B) of Section 122 of the Principal Act, for the protasis “Any electronic commerce operator who”, the protasis and figures “Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under Section 52,” shall be substituted.

**Amendment of 32.
Section 127.**

In Section 127 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words and figures “or Section 74A” shall be inserted.

33.

After Section 128 of the Principal Act, the following Section shall be added, namely:—

**Insertion of new
Section 128A.**

“128A.- Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under Section 73, for certain tax periods.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,—

- (a) a notice issued under sub-section (1) of Section 73 or a statement issued under sub-section (3) of Section 73, and where no order under sub-section (9) of Section 73 has been issued; or
- (b) an order passed under sub-section (9) of Section 73, and where no order under sub-section (11) of Section 107 or sub-section (1) of Section 108 has been passed; or
- (c) an order passed under sub-section (11) of Section 107 or sub-section (1) of Section 108, and where an order under sub-section (1) of Section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be,

on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under Section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of Section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of Section 107 or under sub-section (3) of Section 112 or an appeal is filed by an officer of state tax under sub-section (1) of Section 117 or under sub-section (1) of Section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of Section 108, against an order referred to in clause (b) or

clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

- (2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.
- (3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).
- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under

sub-section (1) of Section 107 or sub-section (1) of Section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.”

Amendment of Section 171. 34.

After sub-section (2) of Section 171 of the Principal Act, the following proviso and Explanation shall be inserted, namely:—

“Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation 1.— For the purposes of this sub-section, “request for examination” shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation 2.— For the purposes of this Section, the expression “Authority” shall include the “Appellate Tribunal”.”

- 35.** After paragraph 8 and before Explanation-1 of Schedule-III of the Principal Act, the following paragraphs shall be inserted, namely:—
- Amendment of Schedule-III.**
- “9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.
10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.”